



DAY

37°

Hi

NIGHT

26°

Low

संक्षेप

एसआईआर के खिलाफ बिहार में विपक्ष का प्रदर्शन, तेजस्वी बोले- बेशर्म हो गया है चुनाव आयोग

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामपंथी दलों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लिए और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कथित वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाए। बताया जा रहा है कि विधायकों को बिना किसी व्यवधान के विधानसभा में प्रवेश करने देने के लिए एक और दरवाजा खोलना पड़ा। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने कहा है कि वे सरकार की पोल खोलने के लिए सदन की कार्यवाही बाधित करेंगे। वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बार-बार इस बात पर आपत्ति जताई है कि सर। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो गरीबों के पास नहीं हैं, तो जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, वो वोटर कैसे बनेंगे। इस तरह से एक बड़ा सवाल उठता है, और आज हम सभी इंडिया एलायंस ने कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव लाने का काम किया है ताकि इस पर विषय चर्चा हो सके। ताकि सारी बातें सामने आ सकें। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कोर्ट में, सड़क पर, सदन में लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग बेशर्म हो गया है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद भी उन्होंने आधार या राशन कार्ड की भूमिका के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।

वर्क-फ्रॉम-होम जॉब का लालच दे ठगें 17.5 लाख, दिल्ली पुलिस ने 4 जालसाजों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना टीम ने वर्क-फ्रॉम-होम जॉब धोतले का पर्दाफाश करते हुए चार ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को झूठे ऑनलाइन जॉब का लालच देकर ठगा और ठगी के पैसों को क्रिप्टोकॉरेसी में बदकर बैंकों और पुलिस को गुमराह किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस घोटाले में एक शिकायतकर्ता से 17.49 लाख रुपये की ठगी की गई। 27 मई 2025 को वसंत कुंज के एक निवासी ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने बताया कि 23 मई 2025 को एक टेलीग्राम आईडी के जरिए उनसे संपर्क किया गया और वेबसाइट रिव्यू करने के लिए 50 रुपये प्रति रिव्यू का लालच दिया गया। कुछ छोटे कार्यों के बाद, ठगों ने उन्हें बिटकॉइन की खरीद-बिक्री जैसे प्री-पेड टास्क करने को कहा और स्क्रीनशॉट भेजने को बोला। शुरुआत में शिकायतकर्ता ने छोटी राशि निवेश की, लेकिन बाद में जालसाजों ने विभिन्न तरीकों से और पैसे जमा करने का दबाव बनाया, यह कहकर कि इससे उनकी कथित कमाई निकाली जा सकेगी। इस तरह शिकायतकर्ता से कुल 17.49 लाख रुपये ठग लिए गए।

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन को लेकर भाजपा हमलावर

विपक्ष कर रहा गुंडागर्दी, भारत कोई धर्मशाला नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बिहार मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की और उन पर गुंडागर्दी का सहारा लेने का आरोप लगाया ताकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों समेत विदेशी लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल सके। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी और तख्तियां लहराकर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने पर मजबूर कर दिया।

विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर किया विरोध-प्रदर्शन

संसद भवन परिसर में विपक्ष के तमाम सांसदों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,



समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव समेत कई बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल रहे। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर जमा हुए और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नारे लगाए। उनका आरोप था कि यह चुनावों में हेराफेरी के समान है। उन्होंने 'एसआईआर: भारतीय अधिकारों की चोरी' और

'एसआईआर: भारतीय गणराज्य को नुकसान पहुंचाना' लिखे हुए पेपर भी पकड़ रखे थे।

भाजपा का विपक्ष पर तीखा हमला

भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध इसलिए कर

रहा है क्योंकि वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भी वोटिंग अधिकार दिलवाना चाहता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'भारत कोई धर्मशाला नहीं है। संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। फिर जांच से आपत्ति क्यों?' उन्होंने दावा किया

कि बिहार के अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। क्या ये नहीं जांचा जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बूथ पर वोटर तो नहीं?'

संसद में हंगामा और कार्यवाही स्थगित

विपक्षी सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करवा दी। वे लगातार नारेबाजी करते रहे- 'एसआईआर वापस लो!' 'संविधान से खिलवाड़ बंद करो!' जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर साधा निशाना और कहा 'विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना रहा है ताकि संस्थाएं उनके इशारे पर चलें। यह संविधान की खुली अवहेलना है।' उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी भारत में वोटिंग का अधिकार मिले।

‘इंडिया’ गठबंधन ने एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया



नहीं चलेगा, एसआईआर नहीं चलेगा' और 'वोटवर्दी बंद करो' के नारे लगाए। कई सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर एसआईआर के विरोध में नारे

लिखे हुए थे। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, 'हम इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रातो-रात लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए।' उन्होंने कहा कि सरकार और

यह लोकतंत्र की हत्या... बिहार में एसआईआर अभ्यास को लेकर भड़कीं प्रियंका गांधी



नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। गांधी ने एएनआई से कहा कि वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और यह गलत है। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि पहले

में लगाया जा रहा 'मतदान प्रतिबंध' संविधान द्वारा प्रदत्त मतदान के अधिकार को छीनने की साजिश है। हम संविधान को कुचलने की हर कोशिश के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने मकर द्वार पर संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर बिहार एसआईआर का विरोध किया और इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की। कई नेता इस संशोधन प्रक्रिया की निंदा करते हुए पोस्टर लिए हुए देखे गए, जिन पर इसे 'भारतीय अधिकारों की चोर', 'लोकतंत्र की मृत्यु' आदि लिखा था। बिहार एसआईआर का मुद्दा विवादास्पद रहा है और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में इस पर चर्चा की मांग की है।

यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग के होटलों-ढाबों पर QR कोड होना जरूरी, योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं



जाए। न्यायमूर्ति एम एम सुरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मंगलवार को कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन होने के कारण होटल या

द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 जून को जारी एक प्रेस विज्ञापि का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हो रही है, जिस पर पहले इस अदालत ने रोक लगा दी थी।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार का निर्देश के अनुसार स्टॉल मालिकों को रैकानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान प्रकट करने के लिए कहा गया है जो कि दुकान, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के निजता के

अधिकार का उल्लंघन है।

इस पर कोर्ट ने कहा, 'हमें बताया गया है कि आज यात्रा का अंतिम दिन है। बहरहाल, निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है। इसलिए, इस समय हम केवल यह आदेश पारित कर सकते हैं कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने के आदेश का पालन करें।'

गौरतलब है कि बीते साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश की सरकारों के उस निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों पर मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम किए जाएं।

शारदा यूनिवर्सिटी ने विभागाध्यक्ष समेत चार प्रोफेसरों को किया निलंबित, पुलिस बल तैनात



प्रशासनिक जांच कमिटी के गठन की मांग की है। पुलिस प्रशासन भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। अब तक हॉस्टल वार्डन और संबंधित विभाग के कई स्टाफ से पूछताछ की जा चुकी है। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय में छात्रों और सामाजिक संगठनों में भारी रोष देखा जा रहा है। लगातार कई संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए

विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावास में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अग्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

गौरतलब है कि गुरुग्राम निवासी छात्र ने बीते शुक्रवार को छात्रावास के अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपने विभाग के प्रोफेसरों और अन्य स्टाफ पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने नोट में दो शिक्षकों का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, अन्य संदिग्ध कर्मचारियों और प्रोफेसरों से भी पूछताछ की जा रही है।

चुनावी सत्यापन पर बंटा सिस्टम, EC ने SC को गिनाई दस्तावेजों की खामियां

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि आधार, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड को मतदाता पात्रता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और नागरिकता का प्रमाण मांगने के अपने संवैधानिक अधिकार पर जोर दिया। सोमवार शाम को प्रस्तुत एक विस्तृत हलफनामे में, चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे प्राप्त शक्तियाँ उसे मतदाता सूची तैयार करने सहित चुनाव के सभी पहलुओं की निगरानी और निर्देशन का पूर्ण अधिकार प्रदान करती हैं।

आयोग ने तर्क दिया कि यह संवैधानिक आदेश, अनुच्छेद 326 के तहत निर्धारित भारतीय नागरिकता की

आवश्यकता सहित मतदाता पात्रता की जाँच करने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता साबित न कर पाना किसी की नागरिकता समाप्त करने के समान नहीं है। यह हलफनामा कई विपक्षी सांसदों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में आया है, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की वैधता, समय और तरीके को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एसआईआर की वैधता की जाँच करने पर सहमति जताई और आग्रह किया कि अगले आदेशों तक मसौदा सूची को अंतिम संगठन न दिया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्रता के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करे।

यूपी में वर्तमान कृषि उत्पादन से तीन गुना अधिक करने की क्षमता: सीएम योगी



आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी यूपी में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है। लगभग तीन करोड़ किसान कृषि पर निर्भर करते हैं। इसके बाद सर्वाधिक रोजगार एमएसएमई दे रहा है। इसके माध्यम से 1.65 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। सीएम ने कहा कि कृषि पलायन का नहीं, बल्कि खुशहाली का माध्यम बने। यह तभी संभव है, जब इस क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान का लाभ किसानों को दे पाएंगे। सीएम ने कहा कि यूपी विकसित होता है तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदारी से प्रयास करता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने उप कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस में शिरकत की। सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन और पुस्तिकाओं-न्यूज लेटर का विमोचन किया। उन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी 'विकसित कृषि-विकसित उत्तर प्रदेश@ 2047' में अपने विचार भी रखे। सीएम ने कृषि वैज्ञानिकों, युवा प्रतिभाओं, एफपीओ आदि का सम्मान भी किया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृषि व कृषि अनुसंधान की दृष्टि से यूपी प्रकृति व परमात्मा की कृपा वाला प्रदेश है। हमारे पास विस्तृत और उर्वरा कृषि भूमि, पर्याप्त जल संसाधन हैं। दुनिया में यूपी एकमात्र ऐसा राज्य होगा, जिसका 86 फीसदी से अधिक भूभाग सिंचित है। यहां केंद्र व राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का बेहतरीन संजाल है। यूपी सरकार पहले से चार कृषि विवि संचालित कर रही है। पांचवां

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने गढ़मुक्तेश्वर के विकास के लिए 19.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर और आस-पास के क्षेत्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को आधुनिक स्वरूप देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 19.50 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत न केवल तीर्थस्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बल्कि आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का विकास भी होगा। इसका लक्ष्य देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना है।प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर गंगा के किनारे स्थित एक पौराणिक एवं धार्मिक स्थल है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसे

संजय सिंह का आरोप—बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण बना ‘ चुनावी घोटाला ’, राज्यसभा में उठाई आवाज़

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित कर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की।सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया एक बड़े “चुनावी घोटाले” का रूप ले चुकी है। यह प्रक्रिया न केवल अपारदर्शी है, बल्कि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला हो रहा है और करोड़ों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद माने जाने वाले मतदाता सूची के नियमित और पारदर्शी पुनरीक्षण को बिहार में जिस प्रकार लागू किया जा रहा है, वह असमानता को बढ़ावा देने वाला है—विशेषकर जब हम इसे

आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देखते हैं। राज्य के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं से ऐसे कठोर दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जिन्हें जुटा पाना गरीब, प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लिए बेहद कठिन है। खासतौर पर आधार कार्ड की अस्वीकार किया जाना, जबकि इसे सरकार स्वयं एक मान्य पहचान दस्तावेज़ मानती रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।संजय सिंह ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची में जुड़े थे, उनसे अब उनके माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो कि ग्रामीण और गरीब वर्गों के लिए लगभग असंभव है। उनके पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है, न स्कूल रिकॉर्ड, और न ही ऐसी प्रशासनिक पहुँच की वे ये दस्तावेज़ तैयार करा सकें।उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जनवरी 2023 में प्रवासी मजदूरों को दूरस्थ मतदान का जो वादा किया गया था, वह अब पूरी तरह विफल

रखी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां के क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप अनुसंधान और प्रकृति-पर्यावरण के अनुरूप शोध को बढ़ाने के लिए और गति दिए जाने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि आपके द्वारा किए गए शोध व विकास के कार्यक्रमों की गति देश व प्रदेश की प्रगति में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

शॉर्ट टर्म, मीडियम व लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर भी चलना होगा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगा तो यूपी कहाँ होगा, उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है। इस पर यूपी ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। हम विजन 2047 की कार्ययोजना के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए कि हमें दो वर्ष में क्या अचीव करना है। हमें 2027, 29 और 35 की भी बात करनी चाहिए। पब्लिक को अपील करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलना होगा। कृषि विवि, कृषि विज्ञान केंद्रों व अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थान इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें।

किसानों को डिमास्ट्रेशन के माध्यम से दें जानकारी

सीएम ने कहा कि कोई फसल एक महीने विलंब होगी और बीज वही पुराना है तो उसके प्रोडक्शन पर भी 30 फीसदी का असर होगा। सीएम ने पूछा कि क्या लेट वेथरयटी के लिए किसानों को तैयार किया। बीज की उपलब्धता व डिमास्ट्रेशन के लिए किसान को प्रशिक्षित किया। यदि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विवि, अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से समय पर सही जानकारी व डिमास्ट्रेशन से बताएंगे नहीं कि इस बीज से इसका इतना प्रोडक्शन लिया जा सकता है तो उसे विश्वास नहीं होगा।

बिना टिकट यात्रियों की पकड़, भ्रष्टाचार में लिप्त सुलतानपुर डिपो के संविदा परिचालक पवन कुमार शुक्ला की सेवा समाप्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सुलतानपुर डिपो में संविदा पर नियुक्त परिचालक पवन कुमार शुक्ला को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया है। पवन कुमार शुक्ला द्वारा इयूटी के दौरान नौ यात्रियों से किराया लेने के बावजूद टिकट जारी नहीं किया गया था। इस गंभीर अनियमितता की पुष्टि जांच में होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।मामले का खुलासा 16 जुलाई 2025 को स्टेट प्लांइंग चैंकिंग स्वावड द्वारा की गई जांच के दौरान हुआ। वाहन संख्या यूपी 42 बीटी 5388 में सव्यक यातायात निरीक्षक पंकज कुमार अम्बेश और रामजगत द्वारा की गई चेंकिंग में पाया गया कि मोतिगरपुर से सुलतानपुर की यात्रा कर रहे 07 यात्री और कालीपुर से सुलतानपुर की ओर जा रहे 02 यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे।

हो गया है और अब उन्हें अस्थायी अनुपस्थिति के आधार पर मतदाता सूची से ही हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यह लोकतंत्र की बुनियादी भावना—सार्वभौमिक मताधिकार—के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 326 का सीधा उल्लंघन है।आप सांसद ने कहा कि यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर चुनावों की निष्पक्षता पर पड़ता है और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को हारा आघात पहुँचता है। उन्होंने मांग की कि बिहार में चल रहे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान की उत्त्‍चस्‍यता जांच कराई जाए और इसे तत्‍काल रोक‍ा जाए, ताकि सभी नागरिकों को निष्‍पक्ष एवं सरल पुनरीक्षण की सुविधा मिल सके।संजय सिंह ने यह दोहराया कि वह चाहते हैं कि सचन इस मुद्दे पर तत्‍काल और गंभीर चर्चा करे, ताकि करोड़ों नागरिकों के मताधिकार की रक्षा की जा सके और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्‍वास कायम रह सके।

महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर मिलेगी छूट... यूपी कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी

महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टॉप में छूट देने का फैसला लिया गया है। एक करोड़ तक की रजिस्ट्री में एक फीसदी स्टॉप तक की छूट दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्रों को स्मार्टफोन नहीं बल्कि सिर्फ टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए दो हजार करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक 60 लाख बच्चों को टैबलेट दिया जा चुका है। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सभी 121 पॉलीटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक अपग्रेड किए जाएंगे। इस पर 6935 करोड़ का खर्च आएगा। इसके सारे उपकरण टाटा कंपनी उपलब्ध करवाएगी। प्रति पॉलीटेक्निक 57 करोड़ रुपये का खर्च होगा। ये कार्याकल्प एक साल में होगा। पशुधन मंत्री ने बताया कि पराग डेयरी को नोएडा में भूखंड को दिया जाएगा। बैठक में लिए विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया गया। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने कैलिए विषय बैठक साथ साझा कार्यक्रम यूपी सरकार चला रही। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास प्रोसेसिंग और निर्यात की व्यवस्था की जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जेवर पर कार्गो का बड़ा सिस्टम डेवलप किया जा रहा। उनाव में हेचरी सीड उपलब्ध कराने के लिए यूसई की कंपनी 4000 करोड़ का निवेश करेगी।

चिनहट में होटल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज खुलासा, युवक–युवती गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। चिनहट थाना क्षेत्र स्थित होटल इशान-इन में सोमवार देर रात हुई गोलीकांड की गुन्थी पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा ली है। होटल के 20 वर्षीय कर्मचारी दिवाकर यादव की हत्या के मामले में चिनहट पुलिस ने मंगलवार को एक युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण निजी रंजिश और आक्रोश था, जो एक विवादित टिप्पणी के बाद उत्पन्न हुआ।घटना सोमवार रात की है, जब दिवाकर यादव, निवासी बलहरी, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर, होटल इशान-इन के बाहर मौजूद था। इसी दौरान वहां पहुंचे आकाश तिवारी और उसकी महिला मित्र पुष्पा गौतम उर्फ पायल से उसका विवाद हुआ। आरोप है कि आकाश और पुष्पा होटल से निकलते समय दिवाकर की टिप्पणी से आहत हो गए थे। इसके बाद दोनों ने “सबक सिखाने” की

बीबीएयू में 25 जुलाई को होगा स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण, 223 पासआउट विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ द्वारा डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पासआउट विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यह वितरण कार्यक्रम 25 जुलाई 2025 को सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ सभागार (SEES हॉल) में आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार मिश्रल विद्यार्थियों को डिवाइस सौंपेंगे।डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) प्रो. नरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना के द्वितीय चरण में 223 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ये वे विद्यार्थी हैं, जिनका डाटा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्यापित किया जा चुका है।

व्यक्ति ने आम के पेड़ से लटक कर दी जान

लखनऊ। गोसाईगंज इलाके के एक गांव में एक ब्यक्ति ने गांव के बाहर आम के पेड़ से रस्सी के सहारे लटक कर जान दे दी। सुबह जब लोगो ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गोसाईगंज पुलिस ने ग्रामीणों के सामने फंदे से उतारकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

गोसाईगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार क्षेत्र के अलिया मऊ गांव के रहने वाले प्रताप रावत (45) ने रात के वक्त घर से गांव के बाहर चला आया। जहां उसने आप के पेड़ से रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि भाई पूर्णवासी के अनुसार मृतक की पत्नी की मौत के बाद से वह दुखी रहता था। वह अकेले ही रहना पसंद करते थे। आत्महत्या का कोई अन्य और कोई कारण नहीं हो सकता था। मृतक के परिवार में दो बेटे गड्डू व सोनू है ।

महिला शक्ति को संगठित कर कांग्रेस को सशक्त बनाने का संकल्प, अजय राय बोले– बदलाव की उम्मीद अब कांग्रेस से

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को नई गति देने और प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्वी जोन की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी जोन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शहला अहारीर ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व विधायक मीना गौतम भी उपस्थित रहें।बैठक में महिला संगठन के जिला, ब्लॉक, वृ्थ और वार्ड स्तर की इकाइयों के गठन पर चर्चा हुई। इसमें दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। तय किया गया कि

डिप्टी सीएम केशव का बड़ा आरोप, ‘कांवड़ यात्रा में अपने लोगों को भेज कर माहौल खराब कर रही सपा’

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि कांवड़ यात्रा में सपा अपने लोगों को भेज कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रजहां भी कोई कांवड़ियों के भेष में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, वह कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को भेजकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है... भाजपा कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है और जब वह कार्रवाई करती है तो तुष्टीकरण करने वालों को इससे



तकलीफ होती है।र बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग उपद्रव और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी

राज्य निर्वाचन आयोग की विशेष कार्य अधिकारी बनीं गरिमा स्वरूप, प्रदेश में नौ पीसीएस इधर से उधर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। यूपी में मंगलवार को 9 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अरविंद कुमार मिश्रा को अपर सूचना निदेशक बनाया गया है जबकि गरिमा स्वरूप को विशेष कार्य अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया है। वह अभी तक बाल विकास पुष्पाहार निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थीं।

इसी तरह विनोद कुमार गौड़ को फरूखाबाद का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। वह अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव के पद पर कार्यरत थे।

अभी तक प्रतीक्षारत डॉ. अलका वर्मा को निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा पद पर नियुक्त किया गया है। गौरव रंजन श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार का जन्मदिन मनाया



आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार, उप-मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का जन्मदिन मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चन्द्र सिंह व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं में प्रदेश महासचिव आनन्द गुप्ता, प्रवक्ता हसीन अहमद खां, प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक

कुमार झा, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग अरविन्द यादव, प्रदेश महासचिव कामिनी शर्मा, प्रदेश सचिव जंग बहादुर, प्रदेश महासचिव प्रवीण सिंह, एमएल प्रसाद, सौरभ शर्मा, डॉ. हरि प्रकाश हरि, मनोष तिवारी, दयाशंकर श्रीवास्तव, जय प्रकाश तिवारी, प्रतीक सिंह, प्रदीप सिंह, प्रमोद सिंह, दिलीप सिंह, सम्पूर्णानन्द पाण्डेय, जितेन्द्र कुमार सोनकर प्रदेश महामंत्री आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

भूजल सप्ताह बना जल संरक्षण का जन आंदोलन, जीवनशैली में लाने का आह्वान



सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया है, जिसके तहत सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और शैक्षणिक भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है।जलशक्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश में भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए सरकार ने अटल भूजल गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने

सचिव, समाज कल्याण विभाग व महानिदेशक, उपाम ने जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए इसके संरक्षण में जनसहभागिता को जरूरी बताया। उन्होंने जल की हर बूंद के संरक्षण, कृषि, उद्योग और दैनिक उपयोग में जल के इष्टतम प्रयोग का आह्वान किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी भूजल उपलब्ध रह सके।अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने

बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं में भूजल संरक्षण शामिल है। इसके लिए विभिन्न कार्यवाही विभाग सतत प्रयास कर रहे हैं। स्कूल-कॉलेजों को भी इसमें वृहद स्तर पर जोड़ा गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फसल विविधीकरण, खेत तालाब निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई, मलिन्य, धान की सीधी बुआई और मृदा संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।समारोह में भूगर्भ जल विभाग के निदेशक सुनील कुमार वर्मा ने राज्य और जनपद स्तर पर आयोजित विविध कार्यक्रमों की जानकारी दी। इनमें क्लाइमेट पर चर्चा, चित्रकला प्रतियोगिता, जल जागरूकता कार्यशालाएँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट और स्कूल आउटरीच कार्यक्रम शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने जल संरक्षण को जनमानस से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है।



डीप स्टेट' : राष्ट्र के विरुद्ध एक अदृश्य युद्ध ...

“डीप स्टेट” — यह शब्द सुनते ही अमेरिका, यूरोप या वैश्विक ख़ुफिया तंत्र की डरावनी छवियाँ उभरती हैं। दुर्भाग्यवश, भारत भी इस अदृश्य सत्ता-संरचना की पकड़ से अछूता नहीं रहा। यह Deep State कोई औपचारिक सत्ता नहीं, बल्कि नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया, एनजीओ, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क और राजनीतिक परिवारों के गठजोड़ से निर्मित वह शक्ति है जिसका उद्देश्य राष्ट्र की नीतियों, संसाधनों, संस्कृति और आम जनमानस को नियंत्रित करना होता है। वर्तमान विपक्ष — विशेषकर कांग्रेस, वामपंथी दल और कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ — कहीं न कहीं इस Deep State तंत्र की कठपुतलियाँ बन चुकी हैं। सत्ता उनके लिए एक साधन नहीं, बल्कि संस्थागत नियंत्रण और आर्थिक लाभ का माध्यम है। सत्ता से बाहर रहते हुए वे इस अदृश्य सत्ता के माध्यम से नीति-निर्माण में हस्तक्षेप करते हैं और येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति के षड्यंत्र रचते रहते हैं। वामपंथी विचारधारा ने दशकों तक विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों पर कब्जा बनाए रखा। न्यायपालिका और नौकरशाही में भी वैचारिक घुसपैठ (ideological infiltration) के उदाहरण बार-बार सामने आते रहे हैं। विदेशी फंडिंग से संचालित NGO न केवल विपक्षी दलों के एजेंडे को बढ़ावा देते हैं, बल्कि शाहीन बाग, किसान आंदोलन, और CAA विरोध जैसे आंदोलनों को संगठित कर राष्ट्र के अंदर संवैधानिक और प्रशासनिक संकट की स्थिति पैदा करते हैं।

भारत में Deep State की जड़ें सबसे गहराई से गांधी-नेहरू परिवार के शासनकाल में पनपीं। इस परिवार ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए न केवल संस्थानों को अपने एजेंडे के अनुसार ढाला, बल्कि नैरिटव कंट्रोल के लिए मीडिया, शिक्षण संस्थानों और सरकारी तंत्र को एक खास वैचारिक दायरे में कैद कर दिया। इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप और संस्थागत दमन ने डीप स्टेट को स्थायी आधारशिला दी।

राजीव गांधी के कार्यकाल में आईटी और टेलीकॉम क्रांति के साथ-साथ पश्चिमी फंडेड एनजीओ का भारत में प्रसार हुआ — जिससे विदेशी एजेंडों को सामाजिक ताने-बाने में गहरी घुसपैठ करने का अवसर मिला। सोनिया गांधी के नेतृत्व में NAC (National Advisory Council) नामक एक समानांतर सत्ता केंद्र स्थापित किया गया, जिसने कई नीतिगत निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से, बगैर संवैधानिक जवाबदेही के, प्रभावित किया। इसी दौर में Ford Foundation, Open Society Foundation (Soros) जैसे विदेशी संस्थानों ने भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया में गहरी पैठ बना ली।

यह Deep State भारत को सीधी जंग से नहीं, बल्कि एक Soft Civil War के ज़रिए तोड़ना चाहता है। इसके हथियार हैं: जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाना; सेना, पुलिस, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थानों पर अविश्वास पैदा करना; और भारतीय संस्कृति को 'पिछड़ापन' बताकर उसे प्रगति का विरोधी साबित करना।

जनता को आपस में लड़ाकर देश में अराजकता और अविश्वास की ऐसी स्थिति पैदा की जाती है, जहाँ गृहयुद्ध जैसे हालात बन जाएँ। यही स्थिति एक 'सत्ता परिवर्तन' की ओर ले जाई जाती है — जहाँ विदेशी ताकतों की कठपुतली सरकार सत्तारूढ़ हो जाए। इनका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट है: भारत की सांस्कृतिक रीढ़ को तोड़ना, उसे पश्चिमी उपभोक्तावाद, वैश्विक बाजारवाद,पश्चिमी उपनिवेशवाद और वामपंथी विचारधारा के अनुसार ढालना — ताकि देश की नीतियाँ भारत के हित में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय एजेंडों के अनुरूप चले।

भारत को आज केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर पर आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। हमें वैचारिक, संस्थागत और संवैधानिक स्तर पर Deep State के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष छेड़ना होगा। जनता को यह समझना होगा कि केवल सरकार बदलना पर्याप्त नहीं होता जब तक कि लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र को खोखला करने वाली संस्थागत शक्तियों को बेनकाब और निष्क्रिय नहीं किया जाता। अब समय है कि भारत का जागरूक नागरिक केवल वोट डालने तक सीमित न रहे बल्कि इस वैचारिक युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाए चाहे वह सोशल मीडिया हो, शिक्षा तंत्र, न्याय प्रणाली, या नीति निर्माण — राष्ट्रवादी चेतना को पुनर्स्थापित करना ही भारत की सच्ची आज़ादी का अगला चरण है। भारत की असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब यह राष्ट्र Deep State के चंगुल से मुक्त होगा। सरकारें चुनते समय हम यह जरूर ध्यान रखें कि जो सरकार आप चुन रहे हैं वह वास्तव में किसके लिए काम करने वाली है? जनता के लिए, या किसी अदृश्य और बाहरी शक्ति के लिए? क्या हम अपने लोकतंत्र की बागडोर वाकई जनता के हाथ में दे रहे हैं, या पदों के पीछे कोई वैश्विक सत्ता तंत्र- Deep State उसे नियंत्रित करने वाला है?

अजब-गजब

पानी के नीचे बसेगी अनोखी दुनिया, जहां आप चलेंगे मछलियों के साथ, हैदराबाद में बनेगा देश का बड़ा टनल



हैदराबाद के प्रसिद्ध नेहरू जूलीजिकल पार्क चिड़ियाघर में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सुरंग मछलीघर यानी अंडरवाटर टनल एक्वेरियम बनने जा रहा है. यह प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार के मीर आलम विकास कार्यक्रम के तहत पूरा किया जा रहा है और पर्यटकों को एक अनोखा समुद्री अनुभव प्रदान करेगा.

यह भारत का पहला और सबसे बड़ा अंडरवाटर टनल एक्वेरियम होगा, जहां विजिटर्स एक प्लास टनल के अंदर से समुद्री जीवों की करीब से देख सकेंगे इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, शार्क, समुद्री कछुए और अन्य जलीय जीव शामिल होंगे. एडवॉन्सड वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि जलीय जीवों को प्राकृतिक वातावरण जैसा महसूस हो. एक्वेरियम के आसपास एजुकेशनल सेक्शन भी बनाया जाएगा, जहाँ समुद्री जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी यह बच्चों और छात्रों के लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है जहां वो एंजॉय के साथ समुंद्र की जीव के बारे में पढ़ भी सकते है.

पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा

ऐसा माना जा रहा है की इस प्रोजेक्ट से हैदराबाद के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. यह एक्वेरियम देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है और एक इनकम का जरिया भी बन जाएगा जिससे हैदराबाद की इकॉनमी को फायदा होगा

तेलंगाना सरकार का लक्ष्य है कि नेहरू जूलीजिकल पार्क को विश्व स्तरीय चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जाए. इसके लिए पहले ही कई अपग्रेड किए गए हैं, जैसे सफारी पार्क, नॉक्टर्नल एनिमल सेक्शन और बच्चों के लिए इंटरएक्टिव जोन अभी इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि यह जल्द ही पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.

संसद में हंगामा मतलब समय और संसाधनों की बर्बादी

डॉ. आशीष वशिष्ठ

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि उम्मीद थी, सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- पहलगाम हमले के आतंक अब तक पकड़े नहीं गए। मारे भी नहीं गए। ट्रम्प 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रूकवाया। सरकार को इन सभी जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा- हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि, एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक और शानदार सफलता की दुर्दुर्घि देशवासियों में ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी जोर-शोर से बज रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता अपने एक एजेंडा और झूठे नैरेटिव के साथ भारत को बदनाम करने के मिशन पर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राहुल गांधी बार-बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट को नुकसान हुआ। दरअसल, वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें पूछना तो यह चाहिए कि हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान को किस तरह तहस-नहस कर दिया? लेकिन राहुल गांधी द्वारा अनाप-शनाप तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना किसी के भी गले नहीं उतर रही है।

वास्तव में, देश के विपक्षी दल और विश्व की ताकतें बखूबी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों ने किस कारनामे की अंजाम दिया है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और मोदी सरकार की दुढ़ इच्छाशक्ति से दुनिया हतप्रभ है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय कहीं राजनीतिक तौर मोदी सरकार को न मिल जाए, इसलिए विपक्ष लगातार रणनीति के तहत अनावश्यक सवाल पूछ कर ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष के इस रवैये से सेना का मनोबल तो गिरता ही है, वहीं देश की उपलब्धियों और गर्व के क्षणों पर भी ग्रहण लगता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब विश्व खासर कांग्रेस किसी विदेशी नेता के बयान या रिपोर्ट के आड़ में संसद को समय बर्बाद कर रहा है। विपक्ष

ब्लॉग

कांवड़ यात्रा के साथ आम यातायात पर भी ध्यान दें

अशोक मधुप

अबसे एक दिन बाद 23 जुलाई को शिवरात्रि का पर्व है। लगभग एक सप्ताह से कांवड़ यात्रा चल रही है। सड़कों पर कांवड़ियों के समूह पवित्र नदियों से जल लेकर अपने गन्तव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के बाद कांवड़ यात्रा पूर्ण हो जाएगी। सड़कों से गुजरते भोले के भक्तों के काफिले अपनी मंजिल पर पहुंचकर अगले छह माह के लिए रूक जाएंगे। जाड़ों में दुबारा शिवरात्रि पड़ेगी, तब ये यात्रा फिर शुरू होगी। फिर कांवड़ियों के काफिले सड़कों पर होंगे। ज्योतिर्लिंग वाले सभी प्रदेशों में इस यात्रा को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की जाती है। अन्य शिवालयों पर भी भारी तादाद में श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। कई बार किसी कांवड़ से किसी के टकराने या कार्वाइए के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कार्वाइए प्राय: हंगामा करते हैं। कई जगह तोड़फोड़ आगजनी आदि पर उतर आते हैं, इसलिए प्रशासन पहले से सचेत रहता है। केंद्र में भाजपा सरकार आने और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार होने के बाद से इस कांवड़ यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इनके लिए आनेजाने के मार्ग निर्धारित होने लगे। इन कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अधिकतर महत्वपूर्ण मार्ग इनके लिए आर्क्षित किए जाने के कारण इन मार्ग के वाहन दूसरे मार्ग पर भेजे जाने लगे। इससे आम लोगों को परेशानी होने लगी। तीन घंटे का रास्ता छह से सात घंटे में पूरा होने लगा। वाहनों की 60 से 70 किलो मीटर ज्यादा चलना पड़ा। वाहनों के ज्यादा चलने के तेल ज्यादा लगा। तेल का ज्यादा लगाना राष्ट्रीय नुकसान है और व्यक्ति की समय की बरबादी। व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न रूप से पूरी हो और दूसरे वाहन और यात्रियों को कोई परेशानी न हो। नियमित यातायात इस यात्रा के दौरान सुगमता से चलता रहे।

आज हालत यह है कि कई दिन से उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर और उत्तरांचल के मार्गों पर दिन में ट्रकों की आवाजाही बंद है। सड़कों के किनारे ट्रकों की लंबीलंबी लाइन लगी है। पूरे दिन वह सड़क किनारे खड़े रहते हैं। रात में उन्हें चलने की अनुमति मिलती है। इस प्रक्रिया से राष्ट्र की कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

शिवरात्रि भगवान शिव का पर्व है। यह पूर्व पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। करोड़ों की संख्या में शिव के उपासक पवित्र नदियों के स्थलों से उनका जल कांवड़ में लेकर आते और शिवालयों पर जाकर चढ़ाते हैं। ज्योतिर्लिंग पर तो शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के साथ उत्तर भारत क्या पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कांवड़ यात्रा कई –दिन चलती है। सड़कों पर कार्वाड़ियों का रेला ही रेला दिखाई देता है। श्रद्धालु कार्वाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराकर पुण्य लाभ पाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कार्वाड़ियों मार्ग पर उनके खाने–पीने की ठहरने आदि की निशुल्क



व्यवस्था करते हैं। भंडारे लगाते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले कार्वाँइए तैयारी करते हैं। कांवड़, उसके सजाने आदि और अपनी यात्रा का सामान खरीदते हैं। अपने साथ चलने वाले वाहन किएए पर लेते हैं। इन पर किएए का म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। कांवड़िए की अलग तरह की भगवा रंग की टी शर्ट चल पड़ी। इसका ही अब लाखों रूपये का कारोबार बन गया। कांवड़ यात्रा से हजारों लोगों का रोजगार चलता है। इस यात्रा पर खरबों रूपये का बिजनेस होता है। इसलिए ये यात्रा होनी चाहिए। इस यात्रा की व्यवस्थाएं भी भव्य होनी चाहिए। कांवड़ियों की व्यापक सुरक्षा और बढ़िया मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। जगहजगह आपातकाल में इनके उपचार के प्रबंध हों। इनकी सुविधा के लिए कोई कसर उठकर नहीं रखी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस व्यवस्था पर स्वयं नजर रखते हैं। वे कार्वाड़ियों पर फूलों की वर्षा भी करते हैं।

उत्तर भारत में सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है। कांवड़ यात्रा के कारण उत्तर भारत में यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। हरिद्वार प्रशासन के अनुसार पिछले साल साढ़े चार करोड़ से ज्यादा शिवभक्त जल लेने हरिद्वार पहुंचे। 2023 में चार करोड़ श्रद्धालु आए थे। ये यात्रा अभी चल रही है, अनुमान है कि इस बार अकेले हरिद्वार से ही कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पांच करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, किंतु कुछ स्थानों पर पूरे

अपने आलोचना धर्म की आड़ में विपक्ष देश की उपलब्धियों और मान—सम्मान पर बेजा टीका—टिप्पणियां करने से बाज नहीं आता। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है। पक्ष—विपक्ष में बहस, तर्क वितर्क और टीका टिप्पणी तो लोकतंत्र की प्राणवायु है। लेकिन सरकार या किसी राजनीतिक दल पर हमला करते करते देश के मान सम्मान को नीचा गिरा देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और देश के संविधान, सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को हासिल नहीं है। भले ही व्यक्ति किसी भी पद या पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हो। हर नागरिक के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव सर्वोपरि, सर्वोसर का देशोत्तरि माथे पर होना ही चाहिए। मामला चाहे देश की सुरक्षा से जुड़ा हो या फिर आर्थिक क्षेत्र की बात हो। विपक्ष सरकार, सेना और संवैधानिक संस्थाओं के बयान पर विश्वास करने की बजाय दूसरे देशों और विदेशी एजेंसियों एवं संस्थाओं के बयान, रिपोर्ट और बयानबाजी पर संसद में हंगामा करता है। असल में संसद सत्र के दौरान देश और दुनिया का ध्यान उस तरफ होता है। इस समय और अवसर का देशहित और जनहित में करने की बजाय विपक्ष सरकार की छवि धूमिल करने, उसकी साख गिराने और अपनी राजनीति चमकाने के लिये करता है।

2023 के बजट सत्र में अदाणी समूह पर हिंडनवर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। अगस्त 2024 में हिंडनवर्ग की एक और रिपोर्ट सामने आई थी। तब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनवर्ग की रिपोर्ट के समय को लेकर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि, पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि हर बार संसद सत्र से ठीक पहले विदेश से एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। इसको आधार बनाकर विपक्ष संसद में हंगामा खड़ा करता है। उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश करार दिया था। अब हिंडनवर्ग के बारे में एक भी शब्द राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता बोलता सुनाई नहीं देता। विपक्ष की राजनीतिक सोच और विचार का समर्थन करने वाला एक तथाकथित तबका देश में मौजूद है। ये लोग भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध के विरोध के लिए 'से नो टू वॉर' कह रहे थे वही लोग आज सीजफायर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब यही लोग कह रहे हैं कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गई। यह लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इरादे और जज्जे से कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह यह साबित कर सकें कि

सीजफायर को स्वीकार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर पीएम साबित किया जा सके। इस तरह की दोहरा रवैया देखकर वास्तव में हंसी आती है कि खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले ये लोग आखिर चाहते क्या हैं?

इस साल बजट सत्र में राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी 119 प्रतिशत, जबकि लोकसभा की 118 प्रतिशत रही। विपक्ष ने नई शिक्षा नीति, मणिपुर के हालात और बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को लेकर सवाल पूछे थे। इस दौरान कुल 16 बिल पास हुए। जट सत्र के आंकड़े भले थोड़े अच्छे दिख रहे हों, पर आमतौर पर संसद से हंगामे की तस्वीरें ही ज्यादा आती हैं। लेकिन बजट सत्र के विपरीत शीतकालीन सत्र में संसद के बहुमूल्य समय और संसाधन नष्ट हुए। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र में कुल 20 बैठकें हुईं। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87 प्रतिशत, राज्यसभा में 41 प्रतिशत रही। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। वहीं, लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएफ इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। शीत सत्र उदाहरण है, जब लोकसभा के 65 से ज्यादा घंटे बर्बाद हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने दोनों पड़ोसियों में शांति कराई। अब तो उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि संघर्ष में कुछ जेट गिरे थे। सरकार पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव होगा। इसी तरह, चुनाव आयोग का स्पेशल इंटीसिव रिवीजन यानी सर केवल वोटिंग लिस्ट की समीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सर की टाईमिंग को सही नहीं माना है, तो सरकार को कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। संसद की कार्यवाही अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। राजनीतिक दल अलग-अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, मगर सदन का अच्छी तरह चलना सभी की जिम्मेदारी है। सत्र को चलाने में हर मिनट ढाई लाख रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं। ऐसे में सदन का काम नहीं करना समय के साथ देश के संसाधनों की भी बर्बादी है। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि संसद के चालू सत्र में हंगामा करके राजनीति चमकाने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने की बजाय संसद के बहुमूल्य समय और संसाधनों का सकारात्मक और सार्थक उपयोग करेंगे।



सीजफायर पर नहीं बन रही बात

कतर में जारी नए दौर की इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम वार्ता एक बार फिर ठप होनी दिख रही है। वार्ता के बीच इजराइली सेना ने रविवार को मध्य गाजा के कुछ हिस्सों से निकासी की नई चेतावनियां जारी की थी, जो युद्ध विराम की कोशिशों को कमजोर करने वाला कदम है।

राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस, 1 हफ्ते में देना होगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए संदर्भ पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। संविधान पीठ में सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल हैं।

संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि अगली सुनवाई में हम समय-सीमा तय करेंगे। कोर्ट 29 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मुद्दा सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं, साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज यह मुद्दा उठाना जल्दबाजी होगी। इसपर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सहमति जताई।

राष्ट्रपति ने SC से 14 संवैधानिक सवालों पर राय मांगी

तमिलनाडु सरकार की ओर से



पेश वकील ने भी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ की योग्यता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हम सीधे प्रभावित होने वाले पक्ष हैं। लिहाजा यह सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 8 अप्रैल को सुनाया था। राष्ट्रपति ने फैसलों के संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत बताया और इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक सवालों पर राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कि उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है?, क्या

राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों के प्रयोग करते समय मंत्री परिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय के लिए किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।

यह निर्णय संविधान के संघीये ढांचे, कानूनों की एकरूपता, राष्ट्र की सुरक्षा और शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) जैसे बहुआयामी विचारों पर आधारित है। क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध

लगाता है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?

राष्ट्रपति ने क्या-क्या कहा?

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग अनिवार्य रूप से बहुकेंद्रीय विचारों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें संघवाद, कानूनों की एकरूपता, राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शामिल है। क्या संविधान की शक्तियों के इस्तेमाल और राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है?

अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर धन विधेयकों को छोड़कर, विधेयक को स्वीकृति प्रदान करनी होगी या जितनी जल्दी हो सके सदन द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा। प्रावधान यह भी निर्धारित करता है कि जब विधेयक पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल

स्वीकृति नहीं देकेगे। राष्ट्रपति ने यह भी पूछा है कि जब देश का संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसले लेने का विवेकाधिकार देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है।

कहां से शुरू हुआ मामला?

यह सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद हुआ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि राज्य के राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चित काल तक देरी किए बिना “जल्द से जल्द” कार्रवाई करनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल “व्यक्तिगत असंतोष, राजनीतिक स्वार्थ, या किसी अन्य बाहरी या अप्रासंगिक विचार” के आधार पर अपनी सहमति नहीं रोक सकते और ऐसी चीजों को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक पर 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा और कहा था कि संवैधानिक ढांचे के तहत “पूर्ण वीटो” (absolute veto) और “पॉकेट वीटो” (Pocket veto) दोनों ही अस्वीकार्य हैं।



महाराष्ट्र में मानसून का लुप्त उठाते सैलानी
सागर बोरा एवं उनके मित्र महेश गना, यशवंत सावंत, देवीदास, पवन तिवारी एवं स्वदेश दूबे सभी ने परिवार के साथ थंब से 6 कि मी. दूर डॉक्टर फार्म में मानसून का लुप्त उठाया।

दिल्ली में 3 साल में 5158 घरों पर चला डीडीए का बुलडोजर, सरकार ने संसद में बताए आंकड़े

नई दिल्ली, एजेंसी। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सरकार से सवाल पूछा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की ओर से कितनी झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ा गया है और इसके कारण विस्थापित हुए लोगों या परिवारों की कुल संख्या कितना संख्या है। इस सवाल का जवाब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिया है और बताया है कि उसने कितनी झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया है।

मंत्रालय ने कहा, ‘डीडीए ने बताया है कि पिछले तीन सालों के दौरान उसने कुल 5 जगह से अतिक्रमण हटाया है। इन ध्वस्तकरण कार्रवाई के चलते 5158

परिवार विस्थापित हुए, जिनमें से कुल 3403 परिवार या 17015 लोग दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की ओर से जारी दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2015 के अनुसार वैकल्पिक पुनर्वास के लिए पात्र पाए गए। जिन लोगों को पात्र पाया गया है उन निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक पुनर्वास दिया गया है।’

मंत्रालय का कहना है कि गोविंद पुरी (कालकाजी) भूमिहीन कैंप के परिवारों को कालकाजी एक्सटेंशन में इन-सीटू स्लम पुनर्वास (आईएसआर) के तहत बसाया गया

है। इनकी संख्या 1896 है। अशोक विहार में जेलरवाला बाग के 1087 झुग्गी-झोपड़ी वाले परिवारों को अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में आईएसआर प्रोजेक्ट (जेलरवाला बाग) में घर दिया गया है। रामपुरा के गोल्डन पार्क के 271 परिवारों को भी स्वाभिमान अपार्टमेंट में घर दिए गए। साथ ही साथ माता जय कौर के 46 परिवारों को यहीं बसाया गया। इसके अलावा आरएमएल के पास कालीबाड़ी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के 103 परिवारों को नरला के सेक्टर G-7 और G-8 घर अलॉट किए गए।

पुनर्वास में DDA को क्या-क्या आई समस्या?

श्रद्धा कपूर ने देखी अहान-अनीत की फिल्म, बोलीं- 'सैयारा' से आशिकी हो गई मुझे

18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर अब 100 करोड़ को पार कर लिया है। इसी बीच 'आशिकी' गर्ल श्रद्धा कपूर ने भी फिल्म देखकर अपना रिएक्शन दिया है।



अहान पांडे और अनीत पट्टा स्टारर फिल्म 'सैयारा' 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रोमांटिक-ड्रामा भरपूर देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने तो फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी 'आशिकी 2' से तुलना की। इसी बीच अब आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर ने भी फिल्म को देखा और अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी। श्रद्धा कपूर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं।

श्रद्धा कपूर ने 'सैयारा' पर दिया रिएक्शन

अभिनेत्री ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में 'सैयारा' देखते हुए दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में श्रद्धा ने लिखा है- सैयारा से आशिकी हो गई है मुझे। इसके बाद उन्होंने मूवी के एक सीन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- इस मोमेंट के लिए मैं 5 बार फिल्म देखूंगी। इसके अलावा श्रद्धा ने कहा- प्योर सिनेमा, प्योर ड्रामा, प्योर मैजिक। उन्होंने अपने फैस को ये भी बताया कि किसी भी फिल्म को देखने के बाद उन्होंने बहुत समय के बाद इमोशनल फील किया है।

'सैयारा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तीन दिनों में 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म 'सैयारा' ने मंडे टेस्ट में भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। संडे को 35.75 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली 'सैयारा' ने सोमवार को 22.5 करोड़ रुपए की कमाई की। आमतौर पर सोमवार को फिल्मों का कलेक्शन काफी नीते आता है। ऐसे में सैयारा का भी कलेक्शन नीचे आया है, लेकिन फिर भी सैयारा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस तरह से 'सैयारा' ने चार दिनों में ही सौ करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। 'सैयारा'

की कुल कमाई 105.76 करोड़ रुपए हो चुकी है।

फिल्म से अहान-अनीत ने किया डेब्यू

आपको बता दें इस फिल्म से अनन्या पांडे के कजिन ब्रदर और चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अपना

बॉलीवुड डेब्यू किया है। उनके साथ फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर अनीत पट्टा नजर आ रही हैं, जिन्होंने पहले बेशक एक्टिंग की है लेकिन इस फिल्म से मुख्य लीड के तौर पर उनका भी डेब्यू हुआ है।



कुशल टंडन टीवी सीरियल की दुनिया का जाना-माना नाम हैं। हाल ही में इस एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में घर में एक फैन घुस गया। इस हरकत से एक्टर काफी गुस्से में हैं।

फैंस के प्यार को वह समझते हैं, मगर घर में घुसने वाली बात से वह दुखी हो गए। इसके पीछे की वजह भी वह अपनी पोस्ट में साझा करते हैं।

अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंता

कुशल टंडन ने इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट की। इसमें वह लिखते हैं, 'आज कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जब घर से बाहर था तो एक फैन बिना परमिशन के घर में घुस गया। मैं साफ कर दूँ कि यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मेरे पैरेंट्स साथ में रहते हैं, उनकी सुरक्षा और शांति मेरे लिए सब चीजों से ऊपर है।'

फैंस को प्राइव्सी की रेस्पेक्ट करने को कहा

आगे कुशल टंडन कहते हैं, 'मैं आपका प्यार समझता हूँ। आपके सपोर्ट के लिए शक्रगुजार हूँ। मगर

पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करना सही नहीं है। मेरे प्राइव्सी की रेस्पेक्ट कीजिए। खासकर जब मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। वस आप अपना प्यार दीजिए लेकिन म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी जरूरी है।'

चर्चा में शिवांगी जोशी से ब्रेकअप

कुशल टंडन की पर्सनल लाइफ की ही बात करें तो इन दिनों शिवांगी जोशी के साथ उनके ब्रेकअप की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में एक्टर ने एक पोस्ट किया था, जिसमें ब्रेकअप से जुड़ी बात लिखी थी। फिर इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। इन दिनों शिवांगी और कुशल टंडन को साथ भी नहीं देखा जाता है।

